RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 22 JANUARY TO 28 JANUARY 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 22 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

बारह हफ्ते में मिट्टी बनने वाला प्लास्टिक ईजाद
Page 3

एक जून से देशभर में लागू होगी 'वन नैशन, वन राशन कार्ड' स्कीम
Page 5

करॉना वायरस से दुनिया में खौफ, अब तक 9 की मौत, भारत में खास जांच
Page 7

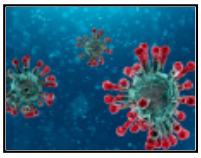

editoria!

भेदभाव का विकास

भारत से जुड़ी विकास की तमाम कहानियों के बावजूद सचाई यह है कि सामाजिक विकास में हमारा मुकाम दुनिया में अब भी काफी नीचे है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की 50वीं सालाना बैठक से पहले जारी 'ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स' की 82 देशों की सूची में भारत को 76वां स्थान दिया गया है। डेनमार्क इसमें टॉप पर है, इसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड का नंबर है। यह इंडेक्स तैयार करने के लिए जिन प्रमुख बातों को ध्यान में रखा गया है, वे हैं- स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, रोजगार, सुरक्षा और सांस्थानिक स्थिति। भारत को जिन बातों का खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई है, उनमें सामाजिक सुरक्षा और समान काम के लिए समान वेतन शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 'अगर कोई देश ऐसा माहौल तैयार करने में सफल रहता है, जहां हर किसी को अपनी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलता है, तो इसका न सिर्फ समाज को सीधा लाभ होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को हर साल अरबों डॉलर का फायदा भी होने लगेगा।' रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी उपयुक्त परिस्थितियां सिर्फ कुछेक अर्थव्यवस्थाओं में ही मौजूद हैं जिनमें चीन, अमेरिका, भारत, जापान और जर्मनी शामिल हैं। साफ है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के जरिए अपना विकास करने की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। आजादी के वक्त हमारा समाज सामंती संरचना में जकड़ा हुआ था। सामाजिक बंधनों के कारण हर किसी के समान रूप से विकसित होने की गुंजाइश नहीं के बराबर थी। मगर हमारे संविधान ने हर किसी को बराबरी के अधिकार दिए और सरकारों को बिना किसी भेदभाव के सबके हित में काम करने का दायित्व सौंपा। बाद में देश में आरक्षण और इस तरह की कई अन्य नीतियां भी अपनाई गईं जिनसे वंचित तबकों को आगे आने के अवसर मिले। इसका फायदा दिख रहा है, लेकिन विकास का लाभ आज भी हर किसी तक नहीं पहुंचा है और सामाजिक-आर्थिक स्तर पर एक गहरी खाई साफ नजर आती है। इसकी कुछ जवाबदेही हमारे देश में पिछले तीन दशकों से अपनाई गई व्यवस्था पर जाती है, जिसमें सरकारों का रोल कम होता गया है और ज्यादातर काम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा चुका है। इससे विकास की रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन साथ में यह नुकसान भी हुआ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के दो स्टैंडर्ड बन गए हैं। निजी क्षेत्र द्वारा दी जा रहीं क्वालिटी सुविधाएं महंगी होने के चलते बेहतर आर्थिक स्थिति वालों को ही मिल पाती हैं। इस तरह साधन संपन्न तबका विकास का ज्यादा लाभ लेने की स्थिति में पहुंच गया है, जबकि सरकारी साधनों पर आश्रित बाकी समाज दिनोंदिन पिछड़ता ही जा रहा है। इस बुनियादी बीमारी का इलाज किए बिना, सिर्फ बीच-बीच में किए जाने वाले राहत उपायों के सहारे हालात कुछ खास नहीं बदलने वाले।

दावोस

IMF के अनुमान घटाने के बावजूद कॉरपोरेट जगत को भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा

दावोस। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ अनुमान को घटाकर 4.8 फीसदी कर दिया है। लेकिन स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) की बैठक में जुटे भारत के कारोबार जगत के दिग्गजों को लॉन्ग टर्म में भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतरी पर भरोसा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट ने इस साल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। आईएमएफ के इस बयान पर भारत के कारोबार जगत के दिग्गजों ने कहा है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म के आउटलुक पर ध्यान देना होगा। कारोबार जगत के दिग्गजों ने कहा कि उन्हें लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था पर भरोसा है, लेकिन अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आर्थिक और नीतिगत सुधार तेज करना होगा।

क्या कहा था आईएमएफ ने

IMF ने भारत के भी ग्रोथ अनुमान को इस वित्त वर्ष यानी 2019-20 के लिए घटाकर 4.8 फीसदी कर दिया है। आईएमएफ का कहना है कि भारत के गिरते जीडीपी ग्रोथ रेट की वजह से ग्लोबल ग्रोथ में कमी आ रही है। स्विट्जरलैंड के शहर में दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच (WEF) की 50वीं सालाना बैठक के दौरान कारोबार एवं उद्योग जगत के कई दिग्गजों ने इस मसले पर बात की। दिग्गजों ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि WEF में भारत 'वन नेशन वन टीम' की तरह अपने को पेश नहीं कर पा रहा। यह सवाल असल में राज्यों और केंद्र के प्रतिनिधियों के अलग-अलग जाने की वजह से उठा है। इन दिग्गजों में टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी,सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी, किर्लोस्कर सिस्टम्स के सीएमडी विक्रम किर्लोस्कर और सेरम्स के सीईओ अदर पूनावाला शामिल थे।

आगे क्या करना है इस पर जोर हो

सीपी गुरनानी ने कहा कि यह वास्तव में बहुत असामान्य बात है कि जो ग्रोथ रेट कभी 8-10 फीसदी हुआ करता था, वह अब 4-5 फीसदी के लेवल पर आ चुका है और इसका वैश्विक तरक्की पर असर पड़ रहा है। इसलिए अब जोर इस बात पर होना चाहिए कि आगे क्या कदम उठाया जाए.उन्होंने कहा, 'ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि इस समय हम क्या कर रहे हैं, बल्कि मध्यम और लॉन्ग टर्म में क्या आउटलुक है।

ऑटो इंडस्ट्री के बुरे दिन बीते!

भारत की विकास दर के बारे में चल रही चर्चा के बारे में जब विक्रम किर्लोस्कर से हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भारत अब कुछ हद तक संरचनात्मक बदलावों से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, 'लोग अब ज्यादा प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तलाश कर रहे हैं जो ज्यादा किफायती हो।' ऑटोमोबाइल सेक्टर की सुस्ती के बारे में किर्लोस्कर ने कहा कि अब यह इंडस्ट्री सुधार के रास्ते पर है। उन्होंने कहा, 'मैं अगली दो-तीन तिमाहियों में ऑटो बाजार के लिए काफी आशावाद देखता हूं।

न्यायिक सुधार क्यों जरूरी है

नीतिगत माहौल पर गुरनानी ने कहा कि आज हर कोई भारत में कारोबार करना चाहता है। अब वैश्विक फर्म भारत में अपना विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन भारत में न्यायिक सुधार की कमी को लेकर उनकी चिंता है। उन्होंने सत्यम के कानूनी विवाद का हवाला दिया जो अभी तक लंबित है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह मामला निबट चुका है। उन्होंने कहा, 'हमें सत्यम के मामले में विरासत में 60अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवाद और 40 घरेलू मामले मिले थे। 18 महीने के भीतर सभी अंतरराष्ट्रीय विवाद सुलझा लिए गए, जबकि एक दशक बीत जाने के बाद भी अभी तक भारत में कोई बड़ा मामला सुलझ नहीं पाया है।' टेलीकॉम कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि न्यायिक सुधार इस साल प्राथमिकता होनी चाहिए। गौरतलब है कि टेलीकॉम सेक्टर को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उन्हें 23 जनवरी तक करीब 93,000 करोड़ रुपये का बकाया समायोजित सकल राजस्व (AGR) जमा करने को कहा है और कोर्ट ने कंपनियों की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया।

एक देश एक टीम क्यों नहीं

कारोबार जगत के दिग्गजों ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि WEF में भारत 'वन नेशन वन टीम' की तरह अपने को पेश नहीं कर पा रहा। केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि अलग-अलग दिख रहे हैं। भारत से दावोस पहुंचने वाले प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के दो और बीजेपी के एक मुख्यमंत्री शामिल हैं। केंद्र सरकार से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और जहाजरानी, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हैं। कंफडेरशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, 'भारत की कहानी वास्तव में राज्यों की कहानी है. मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें एक साथ आना चाहिए. इससे भारत की एक मजबूत छवि पेश होती।

वैश्विक रुख से वायदा कारोबार में कच्चा तेल एक प्रतिशत से ज्यादा गिरा

नयी दिल्ली। एजेंसी

बुधवार को वैश्विक बाजारों में सुस्त रुख के साथ प्रतिभागियों के सौदे कम करने से बुधवार को वायदा कारोबार में कच्चा तेल 48 रुपये गिरकर 4,138 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, फरवरी महीने में डिलिवरी वाला कच्चा तेल 48 रुपये यानी 1.15 प्रतिशत गिरकर 4,138 रुपये प्रति बैरल रह गया। इसमें 21,399 लॉट का कारोबार हुआ। इसी प्रकार, मार्च डिलिवरी वाला कच्चा तेल 43 रुपये यानी 1.03 प्रतिशत कमजोर होकर 4,150 रुपये प्रति बैरल पर रहा। इसमें 612 लॉट का कारोबार हुआ। विश्लेषकों ने कहा कि कमजोर हाजिर मांग के बीच कारोबारियों के सौदे घटाने से वायदा कारोबार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट रही। वैश्विक स्तर पर, वेस्ट टेक्सॉस इंटरमीडिएट कच्चा तेल 0.57 प्रतिशत गिरकर 58.05 डॉलर प्रति बैरल जबकि ब्रेंट कच्चा तेल 0.45 प्रतिशत गिरकर 64.30 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था।

इन तीन सरकारी कंपनियों जल्द का होगा विलय!

Budget से पहले संभव

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी National Insurance Company) लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (United India Insurance) लिमिटेड का ओरियंटल इंश्योरेंस (Oriental Insurance) कंपनी लिमिटेड में विलय हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इन तीनों कंपनियों के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और बजट से पहले या बाद में कभी भी इस विलय की औपचारिक घोषणा हो सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता में सोमवार को इन तीनों कंपनियों के विलय को मंजूरी देने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की बोर्ड की बैठक हुई थी। इसी बैठक में इनके विलय को मंजूरी दी गई। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा विलय को मंजूरी देने से पहले ही ओरियंटल और यूनाइटेड इंडिया का बोर्ड इसे मंजूरी दे चुका था। इसके लिए इन दोनों कंपनियों के बोर्ड की बैठक शुक्रवार को हुई थी. इस विलय में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी भी शामिल हो सकती है।

बता दें कि ट्रेड यूनियंस का दावा है कि सरकार चार सरकारी जनरल बीमा इंश्योरेंस कंपनियों का विलय कर एक बड़ी कंपनी बनाना चाहती है। सरकार इन इंश्योरेंस कंपनियों को एक साथ कर इन्हें मजबूती प्रदान करना चाहती है।

जेटली ने की थी घोषणा

वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीनों सरकारी जनरल बीमा कंपनियों के विलय के प्रस्ताव की घोषणा की थी। लेकिन इन कंपनियों का विलय कई कारणों के चलते जैसे खराब वित्तीय सेहत की वजह से नहीं हो पाया था।

बजट 2020 में किए जा सकते हैं इनको लेकर ऐलान

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट एक फरवरी 2020 को पेश होगा। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के लिए दूसरे दौर की पूंजी डालने की घोषणा कर सकती हैं। कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए सरकार यह कदम उठा सकती है और बजट में इसके लिए घोषणा कर सकती हैं। बता दें कि सरकार ने पिछले महीने यानी दिसंबर में 2019-20 के लिए पहली अनुदान के लिए अनुपूरक मांग में नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में 2,500 करोड़ रुपये डालने की घोषणा की थी।

डीपीआईआईटी ने पेट्रोल पंपों के लिये कागज रहित लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की

नयी दिल्ली। उद्योग और आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने सोमवार को कहा कि उसने पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन (पेट्रोल पंप) के लिये कागज रहित लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की है। इसकी शुरूआत पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के जरिये की गयी। नियमों के तहत इस महीने की शुरूआत में पेट्रोलियम ढुलाई के लिये रोड टैंकर को लेकर कागज रहित आवेदन और लाइसेंस देने की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है। विभाग ने एक बयान में कहा, ''कागज रहित प्रक्रिया शुरू करने के बाद 300 से अधिक लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं।'' बयान के अनुसार इन नियमों के तहत जारी होने वाले लाइसेंस में पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन और पेट्रोलियम ढुलाई के लिये रोड टैंकों की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत से अधिक है। इसमें कहा गया है, ''पेट्रोल पंप लाइसेंस की इस पहल से 70,000 पेट्रोल पंप मालिकों और तेल विपणन कंपनियों को लाभ होगा।''

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद स्थापित बनाई गई

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद स्थापित कर दी है। परिषद केन्द्र सरकार को देश में नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के वास्ते मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उपायों पर जरूरी सलाह देगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, परिषद छात्रों और अन्य लोगों के बीच नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में सुझाव देगी। इसमें कहा गया है कि यह परिषद, सार्वजनिक संगठनों को नवाचार को आत्मसात करने, बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन, संरक्षण और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने, नियामकीय अनुपालन एवं लागत को कम करके कारोबार शुरू करने, उसे संचालित करने, आगे बढ़ाने एवं छोड़ देने को आसान बनाने के उपायों पर भी सुझाव देगी। मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा, परिषद स्टार्ट-अप्स के लिए पूंजी तक पहुंच आसान बनाने, निवेश के लिए घरेलू पूंजी को प्रोत्साहित करने, निवेशकों के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने और मूल प्रवर्तकों के साथ स्टार्ट-अप नियंत्रण रखने के तौर तरीके सुझाएगी।

वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद में केंद्र द्वारा मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों, सफल स्टार्ट-अप संस्थापकों, स्टार्टअप्स में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति शामिल होंगे। इसके अलावा, इसमें स्टार्टअप को सहारा देने उन्हें आगे बढ़ाने उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति भी शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें स्टार्ट-अप अंशधारकों के संघों तथा उद्योग संघों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल दो साल के लिए होगा। मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के नामित सदस्य संयुक्त सचिव के पद से नीचे के नहीं होंगे। ये पदेन सदस्य होंगे। व्यक्तियों के नामों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

आर्थिक नरमी दूर करने के लिये आपूर्ति बाधाओं को दूर करने, कड़े संचालन नियमों की जरूरतः रिपोर्ट

नयी दिल्ली। मुद्रास्फीति में तेजी और धीमी पड़ती वृद्धि दर आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की वृद्धि संभावना को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। सुधारात्मक उपाय के रूप में सरकार को आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के साथ संचालन के और कड़े नियम सुनिश्चित करने की जरूरत है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।अर्थव्यवस्था के बारे में डन एंड ब्राडस्ट्रीट की रिपोर्ट में कहा गया कि भले ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) नवंबर 2019 में सकारात्मक रहा, लेकिन इसके नरम रहने की आशंका है।रिपोर्ट के अनुसार, ''खपत और निवेश में नरमी के साथ उच्च मुद्रास्फीति दबाव, भू-राजनीतिक मसले और आर्थिक वृद्धि में पुनरूद्धार को लेकर अनिश्चितताओं के कारण आईआईपी नरम रह सकती है।''डन एंड ब्राडस्ट्रीट ने आईआईपी के दिसंबर 2019 में 1.5 से 2.0 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान जताया है। सरकारी आंकड़े के अनुसार औद्योगिक उत्पादन में तीन महीनों से गिरावट के बाद नवंबर में इसमें 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका कारण विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि है।कीमत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि असामान्य बारिश के साथ कई राज्यों में बाढ़ तथा भू-राजनीतिक मसलों के कारण सकल मुद्रास्फीति बढ़ी है। वहीं मांग हल्की है।उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 7.35 प्रतिशत पर पहुंच गयी, जो करीब साढ़े पांच साल का उच्च स्तर है। मुख्य रूप से सब्जियों के दाम बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी। इससे पूर्व नवंबर महीने में यह 5.54 प्रतिशत थी। डन एंड ब्राडस्ट्रीट इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री अरुण सिंह ने कहा, ''मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि के कारण मौद्रिक नीति प्रोत्साहन पर कुछ अंकुश लगा है, वहीं राजस्व में कमी से सरकारी व्यय प्रभावित हुआ है।''सिंह के अनुसार वृद्धि में नरमी तथा उसे गति देने के उपायों से राजकोषीय घाटा लक्ष्य से अधिक रह सकता है।उन्होंने कहा, ''सरकार को नरमी दूर करने के लिये छोटे-छोटे कदम उठाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके तहत मुख्य रूप से आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने तथा संचालन के और कड़े नियम सुनिश्चित करने चाहिए।''सिंह ने कहा कि जबतक व्यापार नीति रूपरेखा के तहत इन चिंताओं का समाधान नहीं किया जाता, भारत 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने को लेकर सतत वृद्धि हासिल नहीं कर सकता।

रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले तीन पैसे मजबूत

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

घरेलू शेयर बाजार में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच रुपया बुधवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले शुरुआती कारोबार में तीन पैसे बढ़कर 71.18 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। मुद्रा डीलरों ने कहा कि अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में डॉलर में मजबूती ने रुपये की तेजी को थामने का प्रयास किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया बढ़त के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में बढ़कर 71.18 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। रुपया मंगलवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 71.21 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच , ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.37 प्रतिशत गिरकर 64.35 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 33.43 अंक यानी 0.08 प्रतिशत 41,357.24 अंक पर कारोबार कर रहा था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को निर्यात ऋण विकास योजना को दे सकता है मंजूरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को 'निर्यात ऋण विकास योजना' (निर्विक) को मंजूरी देने पर विचार कर सकता है। इस योजना का मकसद निर्यातकों के लिए ऋण प्रक्रिया को आसान बनाना और ऋण उपलब्धता बढ़ाना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय ने इस योजना के तहत कुछ क्षेत्र के निर्यातकों को उनके द्वारा चुकाए जाने वाले प्रीमियम में सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया है। इस योजना को निर्यात ऋण बीमा योजना भी कहा जा रहा है। इसमें निर्यात ऋण पर मूलधन और ब्याज धन के 90 प्रतिशत तक की राशि को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें माल लदान से पहले या बाद के ऋण को भी बीमा सुरक्षा दी जाएगी। निर्यात ऋण गारंटी निगम अभी 60 प्रतिशत नुकसान पर ऋण गारंटी उपलब्ध कराता है। मंत्रालय ने 80 करोड़ रुपये से कम की रिण सीमा वाले छोटे निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम की दर को घटाकर 0.6 प्रतिशत करने और इससे ऊपर की सीमा वाले निर्यातकों के लिए 0.72 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी किया है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 सितंबर 2019 को की थी।

सीपैट ने भी दी मान्यता

बारह हफ्ते में मिट्टी बनने वाला प्लास्टिक ईजाद

देहरादून। एजेंसी

पॉलीथिन की थैलियां अब पर्यावरण के लिए सिरदर्द नहीं होंगी। प्लास्टिक की ऐसी थैली तैयार कर ली गई है, जो कूड़े में फेंके जाने पर 12 सप्ताह के भीतर स्वतः ही मिट्टी बन जाएगी। इस थैली को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी (सीपैट) ने भी मान्यता दे दी है। इसके बाद ऐसी थैलियों के उत्पादन व प्रयोग पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भी मुहर लगा दी है। तीन माह से भी कम अंतराल में स्वतः ही मिट्टी बनने (कंपोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल) वाली थैली को देहरादून की ही सिद्धी पैकेजिंग कंपनी ने ईजाद किया है। उत्पाद को तैयार करने के बाद उन्होंने इसे टेस्टिंग के लिए सीपैट (चेन्नई) को भेजा था। वहां आठ महीने तक थैली को विभिन्न परीक्षण से गुजारा

गया। परीक्षण के दौरान जब ये थैलियां मिट्टी में तब्दील हो गईं तो इस मिट्टी पर टमाटर व धान उगाए गए। इस मिट्टी में उत्पादन की स्थिति 91 से 92 फीसद रही। जब सीपैट की रिपोर्ट को सीपीसीबी में जमा कराया गया तो यहां से भी उत्पाद को आसानी से हरी झंडी दे दी गई। हालांकि, केंद्रीय बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि इस तरह की थैलियों के उत्पादन में हर थैली पर सीपैट की रिपोर्ट का नंबर, कंपनी का लाइसेंस नंबर व 100 फीसद कंपोस्टेबल/बायोडिग्रेडेबल लिखना जरूरी होगा। ताकि किसी भी तरह की जांच के समय डुप्लीकेसी को पकड़ा जा सके।

इसलिए मिट्टी बन जाती है थैली

यह थैली ब्रेकेबल पॉलीमर चेन का हिस्सा है, जबकि सामान्य पॉलीथिन व पॉली-प्रॉपलीन अनब्रेकेबल पॉलीमर चेन का हिस्सा होती हैं। जो स्वतः नष्ट नहीं हो पाती है। स्वतः मिट्टी बनने वाली थैलियां स्टार्च से बनाई जा रही हैं और यह पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित भी है।

जिसे कपड़ा समझकर बिकवाया जा रहा, वह 100 फीसद प्लास्टिक

उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी जगह सरकारों ने कपड़े जैसे दिखने वाली थैलियों को हरी झंडी दे दी है। हालांकि, हकीकत में यह प्लास्टिक ही है। यानी कि एक प्लास्टिक को हटाकर दूसरे प्लास्टिक की बिक्री कराई जा रही है। यह चौंकाने वाला खुलासा भी सीपैट की जांच में किया गया। देहरादून के ही डोईवाला नगर में सीपैट के स्थानीय केंद्र ने बाजार में प्रचलित ऐसी थैलियों की जांच की। 13 जनवरी 2019 को जारी की गई जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि बाजार में प्रचलित ऐसी थैलियां पॉली-प्रॉपलीन है। जो कि 100 फीसद प्लास्टिक की श्रेणी में आती है। इस तरह के खुलासे से राज्य सरकार के अधिकारी भी सकते में हैं। इस पर शहरी विकास विभाग के अपर सचिव अशोक कुमार पांडे ने सीपैट व सीपीसीबी के प्रमाणीकरण के बाद सभी नगर निकायों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वह कंपोस्टेबल व बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग को ही प्रयोग में लाएं। शेष तरह के कैरी बैग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। इसके साथ ही अशोक कुमार पांडेय का कहना है कि अप्रमाणित कैरी बैग की बिक्री व स्टॉक करने पर विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।

प्लास्टिक से निकलती है हानिकारक मीथेन गैस

यदि सामान्य प्लास्टिक की थैलियों को कूड़े में फेंक दिया जाए तो इससे ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाने वाली मीथेन गैस निकलती है। वहीं, स्वतः नष्ट होने वाली थैली से सामान्य कूड़े की तरह कम हानिकारक और कम मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड निकलती है।

भारत कठिन दौर से गुजर रहा है, नीचे बनी रहेगी आर्थिक वृद्धि दरः अर्थशास्त्री

कोलकाता। भारत कठिन दौर से गुजर रहा है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर अभी नीचे बनी रहेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) के प्राफेसर अजय शाह ने यह कहा।उन्होंने कहा कि इसका कोई त्वरित समाधान नहीं है। हां, अगर समाज के लोग तथा राजनीतिक वर्ग एक-दूसरे के साथ मिल-बैठकर शांति के साथ चर्चा करें तभी इसका समाधान होगा। शाह ने कहा, ''हम इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं और इसका कोई त्वरित समाधान नहीं है। देश की जीडीपी वृद्धि दर नीचे बनी रहेगी।''उन्होंने कहा, ''...भारत में अभी राजनीतिक गहमा-गहमी है। नागरिकों के अधिकार और शक्तियों का अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव होता है।''पूर्व में सेंटर फॉर मानिटरिंग इंडियन एकोनॉमी (सीएमआईई) से जुड़े रहे शाह ने कहा, ''अगर हम समाज के लोग और राजनीतिक वर्ग एक-दूसरे के साथ मिल-बैठकर चर्चा करें तो इसका समाधान मिलेगा।''उन्होंने 1991 से 2011 की अवधि को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल बताया और कहा कि उस दौरान जो आर्थिक वृद्धि हुई, उससे 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए।

शाह ने अपनी पुस्तक 'इन सर्च ऑफ द रिपब्लिक' पर चर्चा के दौरान कहा, ''उसके बाद निजी निवेश में कमी के साथ समस्या शुरू हुई।'' इस किताब को उन्होंने विजय केलकर के साथ मिलकर लिखा है। उन्होंने कहा कि सकल निजी पूंजी निर्माण में 10 प्रतिशत की कमी आयी है। इसे पूरा करना देश की राजकोषीय क्षमता से बाहर है। शाह ने देश में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) लागू करने के तरीके की भी आलोचना की।उन्होंने कहा, ''सरकार को आईबीसी लागू करने में कुछ समय लेना चाहिए। पहले जरूरी बुनियादी ढांचा सृजित करने की आवश्यकता थी।'' इस संहिता के लागू होने के कारण बड़ी संख्या में मामले फंसे हैं।

विदेशीमुद्रा भंडार 5.8 करोड़ डॉलर बढ़कर रिकार्ड 461.21 अरब डॉलर पर

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 5.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 461.21 अरब डॉलर के सर्वकालिक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 3.689 अरब डॉलर बढ़कर 461.15 अरब डॉलर था।आंकड़ों के मुताबिक, समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में गिरावट आने के बावजूद कुल विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई । विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 36.7 करोड़ डॉलर घटकर 427.582 अरब डॉलर रहीं। इस दौरान स्वर्ण भंडार 43.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 28.492 अरब डॉलर हो गया। आलोच्य सप्ताह के दौरान अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण अधिकार 50 लाख डॉलर घटकर 1.442 अरब डॉलर रह गया, जबकि आईएमएफ में आरक्षित निधि 50 लाख डॉलर घटकर 3.697 अरब डॉलर रही।

एटीएफ पर उत्पाद शुल्क के स्वरूप में बदलाव कर सकती है सरकार

नयी दिल्ली। सरकार निकट भविष्य में विमान ईंधन एटीएफ पर लगने वाले शुल्क को मूल्यानुसार लगाने के बजाय विशिष्ट दर से लगाने पर विचार कर सकती है। इससे एटीएफ के दाम में होने वाले उतार चढ़ाव के समय वित्तीय तंगी से गुजर रही विमानन कंपनियों को शुल्क से कुछ राहत मिल सकती है। वर्तमान में एवियेशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर 11 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क लगता है। वहीं विमानन क्षेत्र में क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) योजना को बढ़ावा देने के मकसद से योजना के तहत उड़ने वाली विमानन सेवाओं के लिये एटीएफ पर दो प्रतिशत रियायती दर से शुल्क लिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि एयरलाइंस को इस तरह के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए सरकार आगामी आम बजट में एटीएफ पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क लगा सकती है। यह शुल्क रुपये में प्रति किलोलीटर के हिसाब से लगाया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर पहले से उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दर लागू है। ऐसे में एटीएफ पर भी इसी तरह का शुल्क लगाने की गुंजाइश बनती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। मूल्यानुसार शुल्क संबंधित उत्पाद के मूल्य के हिसाब से लगता है। ऐसे में यदि उत्पाद का दाम बढ़ता है या घटता है तो उस पर भुगतान की जाने वाली शुल्क राशि भी बढ़ती- घटती है। जबकि विशिष्ट उत्पाद शुल्क मूल्य के अनुरूप घटता- बढ़ता नहीं है यह उत्पाद की मात्रा के अनुरूप तय किया जाता है। इस शुल्क ढांचे को स्पष्ट करते हुए सूत्रों ने कहा कि यदि एटीएफ की उत्पादन लागत 100 रुपये प्रति किलोलीटर है तो रिफाइनरी के गेट पर यह 11 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के साथ 111 रुपये बैठेगी। यदि लागत बढ़कर 110 रुपये पर पहुंच जाती है तो उत्पाद शुल्क की दर 12 रुपये हो जाएगी। विशिष्ट उत्पाद शुल्क की स्थिति में लागत बढ़ने पर भी यह 11 रुपये प्रति किलोलीटर ही रहेगी। पेट्रोल और डीजल पर पहले से विशिष्ट उत्पाद शुल्क लगता है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क की दर 21.16 रुपये लीटर और डीजल पर 15.83 रुपये लीटर है।

भारत, चीन में विश्वास का स्तर ज्यादा, दुनियाभर में सरकार, मीडिया पर भरोसा हुआ कमः सर्वे

दावोस। एजेंसी

असमानता बढ़ने के साथ दुनिया भर में विभिन्न संस्थानों को लेकर भरोसा टूट रहा है। खासकर सरकारों और मीडिया को लेकर भरोसा कम हुआ है। हालांकि, चीन और भारत दो ऐसे देश है जहां सरकार और दूसरे संस्थानों के प्रति विश्वास का स्तर अन्य देशों के मुकाबले ऊंचा है। एक सर्वेक्षण में यह कहा गया है। मंगलवार को जारी 'एडेलमेन ट्रस्ट बैरोमीटर' में यह कहा गया है। वहीं, दूसरी तरफ भारत की गिनती उन देशों में प्रमुख है जहां रोजगार खोने को लेकर चिंता सर्वाधिक है। चीन उसकी आबादी के बड़े हिस्से के बीच भरोसे के मामले में सूची में अव्वल है जबकि इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। वहीं रूस दोनों मामलों में निचले पायदान पर रहा है।इस सर्वे में कहा गया है कि मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था और लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति के बावजूद हर विकसित बाजार में बहुसंख्यक प्रतिभागियों को इस बारे में भरोसा नहीं है कि उनकी स्थिति पांच साल में बेतहर होगी और 56 प्रतिशत का मानना है कि मौजूदा रूप में पूंजीवाद भलाई करने के मुकाबले नुकसान ज्यादा कर रहा है। एडेलमैन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रिचर्ड एडेलमैन ने कहा, ''हम भरोसे की कमी की स्थिति में जी रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''हमने 20 साल पहले भरोसे का आकलन शुरू किया। आर्थिक वृद्धि ने विश्वास को बढ़ाया है। यह एशिया और पश्चिम एशिया में बना हुआ है लेकिन विकसित बाजारों में ऐसा नहीं है। विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में असमानता अब महत्वपूर्ण कारक बन गई है। आशंका उम्मीदों का गला घोंट रही है। लंबे समय से जो यह धारणा रही है कि कठिन मेहनत से हम ऊपर जाएंगे, वह अब महत्वहीन हो रहा है।'' सर्वे के अनुसार, ''यह चिंता व्यापक स्तर पर है। वैश्विक स्तर पर ज्यादातर कर्मचारी (83 प्रतिशत) स्वचालन, लंबे समय से चली आ रही नरमी, प्रशिक्षण का अभाव, सस्ती विदेशी प्रतिस्पर्धा, आव्रजन और अस्थायी रोजगार वाली अर्थव्यवस्था के कारण नौकरी जाने की आशंका को लेकर चिंतित हैं।'' इसमें कहा गया है कि सर्वे में शामिल लोगों में से 57 प्रतिशत प्रतिभागी मान-सम्मान जाने को लेकर चिंतित हैं। उन्हें भय है कि उन्हें जो सम्मान मिल रहा है, उसमें कमी आ सकती है। करीब दो तिहाई लोगों का मानना है कि प्रौद्योगिकी में बदलाव काफी तेज है। 76 प्रतिशत ने कहा कि फर्जी खबर को हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है और वे इसको लेकर चिंतित हैं।सर्वे के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि सीईओ आगे बढ़कर अगुवाई करेंगे। 92 प्रतिशत कर्मचारियों ने कहा कि सीईओ को फिर से प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी नीति परक उपयोग और आय असमानता समेत वर्तमान मसलों पर बोलना चाहिए।सर्वे में सरकारों को अयोग्य और बेईमान माना गया है लेकिन पर्यावरण संरक्षण और आय असमानता दूर करने के मामले में कंपनियों के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद माना गया है।इसमें मीडिया को भी अयोग्य और बेईमान माना गया है। सर्वे में शामिल लोगों में से 57 प्रतिशत का मानना है कि मीडिया अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा। हालांकि, सर्वे में माना गया है कि कंपनियां और सरकारें उच्च भरोसा हासिल करने के लिये कदम उठा सकती हैं। प्रतिभागियों को उम्मीद है कि कंपनियां सही वेतन और प्रशिक्षण देने पर ध्यान देगी।

परंपरागत 'हलवा रस्म' के साथ बजट दस्तावेजों की छपाई का काम शुरू

नयी दिल्ली। परंपरागत 'हलवा रस्म' के साथ वित्त वर्ष 2020-21 के बजट दस्तावेजों की छपाई का काम सोमवार को शुरू हो गया। समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट एक फरवरी 2020 को पेश किया जाएगा। हलवा रस्म के तहत एक बड़ी कड़ाही में 'हलवा' तैयार किया जाता है और वित्त मंत्रालय के सभी कर्मचारियों में बांटा जाता है। समारोह में वित्त सचिव राजीव कुमार, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे, आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती , दीपम विभाग में सचिव तुहिन कांत पांडे और व्यय सचिव टी . वी . सोमनाथन ने भी भाग लिया। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा , 'बजट की गोपनीयता को बनाये रखने के लिए बजट प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को आम बजट पेश होने तक नार्थ ब्लॉक स्थित छपाई खाने में ही रहना होता है। ' संसद में बजट पेश होने तक अधिकारियों को अपने परिजनों तक से बातचीत करने अथवा मिलने की अनुमति नहीं होती है। वित्त मंत्रालय के कुछ बहुत वरिष्ठ अधिकारियों को ही घर जाने की अनुमति होती है। हलवा समारोह के बाद , वित्त मंत्री ने छापेखाने का दौरा किया और बजट की मुद्रण प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली।

ICICI बैंक ने दी बिना कार्ड एटीएम से कैश निकासी की सुविधा

नई दिल्ली। एजेंसी

ICICI बैंक ने मंगलवार को बिना कार्ड के एटीएम से निकासी सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत लेनदेन सीमा प्रतिदिन 20,000 रुपये होगी। बैंक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस सेवा से ग्राहक बैंक के 15,000 से अधिक एटीएम से धन निकासी कर सकेंगे। ग्राहक आई-मोबाइल पर रिक्वेस्ट के जरिए कैश निकाल सकते हैं। ICICI बैंक ने एक बयान में कहा, 'यह बिना डेबिट कार्ड उपयोग के नकद निकासी की सरल और सुगम सुविधा प्रदान करता है।' इस सेवा का उपयोग उस समय किया जा सकता है जब ग्राहक डेबिट कार्ड साथ नहीं रखना चाहता। इस सुविधा के तहत दैनिक लेनदेन सीमा 20,000 रुपये तय की गई है।

एसबीआई के ग्राहकों को हासिल है सुविधा

पिछले साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भी अपने ग्राहकों के लिए इस सेवा की शुरुआत की थी। एसबीआई ग्राहक योनो ऐप की मदद से बिना डेबिट कार्ड पैसा निकाल सकते हैं। यह बेहद आसान होने के साथ ही सुरक्षित भी है। डेबिट कार्ड के जरिए धोखाधड़ी की बढ़ती शिकायतों के बाद बैंक कार्डलैस सुविधा पर जोर दे रहे हैं।

पी-75 आई परियोजना के लिए कंपनियों का चयन

5100 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को मंजूरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए भारत में छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से जुड़ी 50 हजार करोड़ रुपये की परियोजना के वास्ते एक महत्वपूर्ण कदम के तहत मंगलवार को दो भारतीय और पांच बड़ी विदेशी कंपनियों का चयन किया तथा साथ ही 5,100 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को भी मंजूरी प्रदान कर दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पनडुब्बी निर्माण के लिए चुनी गईं दो भारतीय कंपनियों में एल एंड टी समूह और सरकारी मझगांव डॉक्स लिमिटेड (एमडीएल) शामिल हैं।पनडुब्बी निर्माण की परियोजना को 'मेक इंन इंडिया' पहल के तहत सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि पी-75 आई नामक इस परियोजना के लिए मजबूत दावेदार मानी जा रही अडानी डिफेंस योग्यता मानदंडों के मूल्यांकन के बाद उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा उपयुक्त नहीं मानी गई। इस बड़ी परियोजना को महत्वाकांक्षी रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें चयनित निजी कंपनियों को मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ भागीदारी में भारत में पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों जैसे सैन्य साजो-सामान के निर्माण में उतारा जा रहा है।रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षा खरीद परिषद (डीएएसी) ने स्वदेशी स्रोतों से 5,100 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। इनमें सेना के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और भारतीय उद्योग द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्मित की गईं अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां शामिल हैं।'' अधिकारियों ने बताया कि प्रणालियां रेगिस्तान और मैदानी इलाकों में इस्तेमाल की जाएंगी और ये जमीनी टुकड़ियों को समग्र इलेक्ट्रॉनिक मदद तथा जवाबी कदम क्षमताएं उपलब्ध कराएंगी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि डीएसी ने भारतीय रणनीतिक भागीदारों और संभावित मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के चयन को भी मंजूरी दी जो रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत भारत में छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण का कार्य करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की बैठक में ये निर्णय किए गए जिनमें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और अन्य शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे।

पी-75 आई परियोजना के लिए चुनी गईं पांच विदेशी कंपनियों में थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (जर्मनी), नवांतिया (स्पेन) और नेवल ग्रुप (फ्रांस) भी शामिल हैं। भारतीय नौसेना पानी के भीतर अपनी मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए छह परमाणु पनडुब्बियों सहित 24 नयी पनडुब्बियां खरीदना चाहती है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद डीएसी की यह पहली बैठक थी।

वैश्विक तापमान बढ़ाने में भारत का योगदान नहीं, ईंधन मामले में निभा रहा जिम्मेदारीः गोयल

दावोस। एजेंसी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक तापमान बढ़ाने में भारत की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है। इसके बावजूद जीवाश्म ईंधन के मामले में भारत जवाबदेही के साथ काम कर रहा है। वहीं कार्बन उत्सर्जन में बड़ी भूमिका निभाने वाले पश्चिमी देश पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं।विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में गोयल ने यह भी कहा कि भारत लोगों के साथ निवेशकों के हितों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश निवेशकों का स्वागत करता है और उनके लिये नियमन को और आसान बना रहा है।उन्होंने कहा, ''जब संचालन व्यवस्था और आसान नियमन की बात आती है, भारत कई साल तक नुकसान की स्थिति में रहा लेकिन हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद जो भी विरासत में मसले मिले थे, उनका समाधान किया...।''

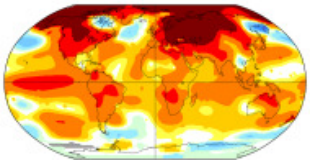

रेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे गोयल ने कहा, ''हम अपने लोगों को सही अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं ओर साथ ही निवेशकों के हितों की भी रक्षा करना चाहते हैं।'' उन्होंने कहा, ''हम हमेशा भारत को निवेशकों के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बुनियादी ढांचा में सुधार के लिये दुनिया भर में अपने दोंस्तों से बातचीत कर रहे हैं...।'' पर्यावरण के मसले पर मंत्री ने कहा, ''भारत का ग्लोबल वार्मिंग में न्यूनतम योगदान रहा है। लेकिन इसके बावजूद जीवाश्म ईंधन के मामले में काफी जवाबदेह है। वहीं पश्चिमी दुनिया का कार्बन उत्सर्जन में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है, लेकिन वे वास्तव में इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे। हमने भारत में एलईडी बल्ब कार्यक्रम के जरिये इस दिशा में काफी कुछ किया है।'' उन्होंने कहा कि हम जीवाश्म ईंधन के मामले में जवाबदेही से काम कर रहे हैं और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं।

नोटबंदी से पकड़ा गया जूलर्स का खेल

2-3 लाख की आमदनी दिखाने वालों ने बैंकों में अचानक डाले करोड़ों रुपये

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद देश के कई जूलर्स ने बेहिसाब नकदी बैंकों में जमा कराई थी। सालभर में 2-3 लाख रुपये की आमदनी दिखाने वाले जूलर्स ने अचानक करोड़ों रुपये कहां से जमा करा दिए? इसका अब उनके पास जवाब नहीं है। आंकड़ों के विश्लेषण के बाद वित्त मंत्रालय ने इन मामलों की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। इन कारोबारियों ने जितनी नकदी जमा की है वह उनके आय के ज्ञात स्त्रोतों से मेल नहीं खाती है। सूत्रों ने कहा कि जांच के दायरे में आए इन जौहरियों ने आकलन वर्ष 2017-18 के अपने आयकर रिटर्न में इस तरह के लेनदेन की कोई जानकारी नहीं दी है।

94 हजार पर्सेंट अधिक जमा

सूत्रों का कहना है कि नोटबंदी के दौरान कई जूलरी कारोबारियों ने बैंकों में बेहिसाब नकदी जमा की। इस नकदी के बारे में वह अपने बिक्री कारोबार से प्राप्त आय या कोई अन्य संतोषजनक ब्योरा नहीं दे पाए। एक मामले में तो जमा की गई राशि उस कारोबारी की पिछले साल की आय के मुकाबले 93,648 प्रतिशत ज्यादा है।

- सूत्रों का कहना है कि नोटबंदी के दौरान कई जूलरी कारोबारियों ने बैंकों में बेहिसाब नकदी जमी की
- एक मामले में जमा की गई राशि उस कारोबारी की पिछले साल की आय के मुकाबले 93,648% ज्यादा
- जिसके खाते में एक साल पहले 2.64 लाख रुपये की नकदी थी, नोटबंदी के बाद खाते में 6.22 करोड़ रुपये

गुजरात का है यह केस

सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मामला गुजरात से सामने आया है। यहां एक आभूषण कारोबारी ने नोटबंदी (9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016) के दौरान 4.14 करोड़ रुपये नकद जमा किए हैं। जबकि इससे एक साल पहले इसी अवधि में उस कारोबारी की जमा राशि 44,260 रुपये ही थी। इसमें 93,648 प्रतिशत की वृद्धि सामने आई है।

2-3 दिन में ही जमा कराए करोड़ों

सूत्रों के मुताबिक, आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कई आभूषण कारोबारी जिन्होंने रिटर्न में अपनी आय 5 लाख से कम दिखाई है उन्होंने नोटबंदी के दौरान 2-3 दिन में ही करोड़ों रुपये की नकदी जमा की। आंकड़ों की छानबीन से पता चलता है कि एक आभूषण कारोबारी जिसकी सालाना आय सिर्फ 1.16 लाख रुपये थी उसने तीन दिन में 4.13 करोड़ रुपये जमा किए।

लाख से करोड़ों में पहुंचे

इसी प्रकार 2.66 लाख रुपये की आय वाले एक जौहरी ने दो दिन में 3.28 करोड़ रुपये और 5.4 लाख रुपये की आय दिखाने वाले एक अन्य सुनार ने 2.57 करोड़ रुपये जमा कराये। एक अन्य मामले में एक आभूषण कारोबारी जिसकी रिटर्न में सालाना आय सिर्फ 3.23 करोड़ रुपये थी, उसने 52.26 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा किए।

नहीं दे पा रहे हैं जवाब

सूत्रों ने कहा कि कारोबारी के पास 9 नवंबर 2015 में सिर्फ 2.64 लाख रुपये की नकदी थी जबकि 9 नवंबर 2016 तक उसके पास 6.22 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी हो गई। नकदी में अचानक 23,490 प्रतिशत वृद्धि को लेकर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।

दूसरी कंपनी का खाता अपलोड किया

सूत्रों के अनुसार एक अन्य मामले में आभूषण कारोबारी ने विभिन्न अज्ञात ग्राहकों से 20,000 रुपये से कम नकदी प्राप्त की और उसे बैंक खाते में जमा कर दिया। उसके बाद यही राशि उसी ग्राहक को बिना किसी कारण के लौटा दी गई। सूत्रों ने बताया कि सबसे मजेदार मामला यह देखा गया कि कुछ ने आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले फार्म 3सीबी के साथ ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करते हुए कुछ कारोबारियों ने अपना नफा-नुकसान खाता अपलोड करने के बजाय किसी दूसरी कंपनी का खाता अपलोड कर दिया।

एक जून से देशभर में लागू होगी 'वन नैशन, वन राशन कार्ड' स्कीम

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में आने वाली पहली जून से वन नैशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उपभोक्ता एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम 1 जून से इस योजना को देशभर में लागू करेंगे। बता दें कि इससे पहले पिछले साल केंद्रीय मंत्री ने 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना का पायलट प्रॉजेक्ट चार राज्यों में लागू किया था। इसके तहत आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और गुजरात, महाराष्ट्र के बीच कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी गई थी, जिसका उद्घाटन पासवान ने ऑनलाइन किया था। तब उन्होंने कहा था कि पायलट प्रॉजेक्ट के सफल रहने पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत राशन कार्ड पूरे देश में मान्य हो जाएंगे।

भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम

अब केंद्रीय मंत्री ने ऐलान किया है कि इस साल की पहली जून से वह इस योजना को देशभर में लागू करेंगे। इससे किसी भी राज्य का राशन कार्डधारक किसी भी अन्य राज्य में राशन की दुकानों से सस्ती कीमतों में चावल और गेहूं खरीद सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे ना केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, बल्कि रोजगार या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इस बदलाव से एक से अधिक कार्ड रखने की संभावना भी खत्म हो जाएगी।

सरकार, वाहन उद्योग बीएस-6 मानक वाले ईंधन, वाहन पेश करने को तैयार

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार और वाहन उद्योग एक अप्रैल 2020 की समयसीमा के भीतर भारत-चरण-6 मानक वाले ईंधन और वाहन उतारने को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। यह बात अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय की अधिकार प्राप्त प्रदूषण नियंत्रण समिति को बतायी। भारत चरण उत्सर्जन मानक नियमन हैं जिसका मकसद मोटर वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर लगाम लगाना है। बीएस-6 या भारत चरण- 6 नया उत्सर्जन मानक हैं जिसे देश के सभी वाहनों को अपनाना होगा। बीएस-6 ईंधन लागू करने और उसके अनुकूल वाहनों को लेकर तैयारी की समीक्षा बैठक के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों ने ईपीसीए (पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण) को बताया कि बीएस-6 ईंधन एक अप्रैल से उपलब्ध होगा। ईपीसीए की सदस्य सुनीता नारायण ने कहा, "वाहन उद्योग ने ईपीसीए से कहा है कि उन्होंने समयसीमा के भीतर काम पूरा करने के लिये काफी प्रयास किया है। मॉडल पहले ही पेश किये जा चुके हैं। कुछ अन्य मॉडल को जल्द ही पेश किया जाएगा।" नारायण ने कहा, "बीएस- पांच ईंधन मानक वाले वाहनों का पंजीकरण एक अप्रैल को बंद कर दिया जायेगा। यह अंतिम समय सीमा है।" उधर पेट्रोलियम मंत्रालय ने समिति से कहा है कि वह एक अप्रैल से पूरे देश में बीएस-छह मानक वाले ईंधन की आपूर्ति के लिये तैयार हैं।

चमड़ा निर्यात बढ़ाने के लिए बजट में सहायक उपायों की उम्मीद: सीएलई

नयी दिल्ली। चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) ने मंगलवार को कहा कि आगामी बजट में उन्हें सरकार से इस श्रम आधारित उद्योग से निर्यात बढ़ाने के लिए समर्थनकारी उपायों की घोषणा किये जाने की उम्मीद है। सीएलई के अध्यक्ष अकील अहमद पनारुना ने कहा, "एक विशाल और बढ़ते वैश्विक बाजार के साथ, हम इस वर्ष विकास के अच्छे अवसर देख रहे हैं। हम वर्ष 2020-21 के आगामी बजट में और विदेश व्यापार नीति में भी इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त समर्थनकारी उपायों की उम्मीद कर रहे हैं जो हमारे विकास को और आगे ले जाएगा।" चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान चमड़े और चमड़ा उत्पादों का निर्यात 7.55 प्रतिशत घटकर 3.6 अरब डॉलर रह गया। वर्ष 2018-19 में 5.7 अरब डालर का निर्यात हुआ था। उन्होंने कहा कि बिना चमड़े वाले जूते-चप्पल के निर्यात में वृद्धि की व्यापक संभावना है और परिषद ने सरकार को कच्चे माल के आयात पर शुल्क में छूट प्रदान करने का सुझाव दिया है।वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि दुनियाभर में चमड़े के जूते-चप्पल के कुल आयात में भारतीय निर्यात का मूल्य के संदर्भ में 39 प्रतिशत और मात्रा के मामले में 14 प्रतिशत हिस्सा है। उन्होंने कहा कि परिषद ने वैश्विक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। उन्होंने कहा, "भारतीय अंतरराष्ट्रीय चर्म मेला (आईआईएलएफ) का 35 वां संस्करण चेन्नई में 31 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसमें चमड़ा उद्योग के कच्चे माल से लेकर चमड़ा उद्योग से संबंधित उत्पादों की पूरी श्रृंखला प्रदर्शित करने के अलावा मशीनरी, रसायन और विभिन्न घटकों के अलावा चमड़ा उद्योग से संबंधित उत्पादों की पूरी श्रृंखला प्रदर्शित की जायेगी।" अहमद ने कहा कि इस मेले में 300 से अधिक घरेलू और 150 विदेशी कंपनियां भाग लेंगी।परिषद चेन्नई में 1-3 फरवरी से डिजाइनर मेले का भी आयोजन कर रही है, जिसमें 10 देश भाग ले रहे हैं।

सरकार अब प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर कर रही विचार

नयी दिल्ली। एजेंसी

उत्पादक क्षेत्रों से नई प्याज की आवक शुरू होने के बाद सरकार अब प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है। मंडियों में नई प्याज की आवक शुरू होने के साथ अब प्याज के दाम नीचे आने लगे हैं। एक अधिकारी ने बताया, "नये प्याज की आवक से कीमतों में नरमी आएगी, इसलिए निर्यात प्रतिबंध हटाने की आवश्यकता है।" पिछले महीने एक समय प्याज की कीमत 160 रुपये किलो तक पहुंच गई थी लेकिन अब यह किस्म और अलग अलग स्थानों की प्याज के मुताबिक 60 से 70 रुपये किलो रह गई है।

नई प्याज की आवक जनवरी से मई तक होगी। सितंबर 2019 में सरकार ने घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। व्यापारियों पर भी स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी गई थी। महाराष्ट्र में प्याज की काफी पैदावार होती है लेकिन वर्षा के मौसम में यहां भारी बारिश होने और राज्य में आने से नुकसान होने की वजह से दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में खुदरा प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में अधिक बारिश से फसल वर्ष 2019-20 के खरीफ और खरीफ की देर से हुये प्याज उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट रही।

माथे की लकीरें बताती हैं भविष्य

माथे की लकीरों का कनेक्शन भाग्य से जुड़ा है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के माथे की लकीरों को देखकर यह ज्ञात किया जा सकता है कि वह कितना भाग्यशाली है। माथे की ये लकीरें व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य की ओर इशारा करती हैं।

धन से जुड़ी माथे की पहली लकीर

सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति के माथे की पहली लकीर का संबंध धन से होता है। यह लकीर भौं के निकट बनती है। इसे धन की लकीर भी कहते हैं।

जिस व्यक्ति की धन की यानी माथे की पहली लकीर जितनी स्पष्ट होगी, वह व्यक्ति उतना ही धनवान होगा।

माथे की दूसरी लकीर सेहत की देती है जानकारी

व्यक्ति के स्वास्थ्य जीवन से जुड़ी है माथे पर बनी दूसरी लकीर। यह लकीर भौंहों के निकट की लकीर के बाद दूसरी लकीर होती है। अगर माथे की दूसरी लकीर गाड़ी और साफ दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन अच्छा होगा। इसके विपरीत यह लकीर पतली और हल्की होती है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

भाग्य से है माथे की तीसरी लकीर का कनेक्शन

माथे पर पड़ने वाली नीचे से तीसरी लकीर भाग्य की लकीर होती है। खास बात ये है कि यह लकीर बहुत ही कम लोगों के माथे पर होती है। जाहिर सी बात है कम लोग ही भाग्यशाली होते हैं। अगर यह लकीर माथे पर बनी होती है तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है।

जीवन के उतार-चढ़ाव से जुड़ी है चौथी

माथे पर बनने वाली चौथी लकीर का संबंध जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव से होता है। हालांकि ये लकीर 26 से 40 वर्ष तक के उतार-चढ़ाव और संघर्ष के बारे में बताती है। ऐसे व्यक्ति चालीस की उम्र के बाद सफलता की बुलंदियों में होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का आर्थिक जीवन भी अच्छा होता है।

पांचवीं लकीर का है ये मतलब

माथे पर बनने वाली पांचवीं लकीर को खतरनाक माना जाता है। यह लकीर जीवन में तनाव और चिंता को दर्शाती है।

छठी लकीर वाले करते हैं अप्रत्याशित उन्नति

माथे पर छठी लकीर नाक की सीधी तरफ ऊपर जाने वाली लकीर को कहते हैं। इसे दैवीय लकीर कहा जाता है। क्योंकि यह लकीर संकेत देती है कि व्यक्ति के ऊपर दैवीय कृपा है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन में प्यार का रस घोलती हैं ये फेंगशुई टिप्स

फेंगशुई चीनी ज्योतिष में वास्तु दोष को खत्म करने का बेहतरीन उपाय है। फेंगशुई टिप्स जीवन की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। हमारे वातावरण में चारों ओर कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती हैं और ये निगेटिव पावर हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। परंतु घर या कार्यस्थल पर फेंगशुई उपाय के कारण नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव शून्य हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। यहां कुछ ऐसे फेंगशुई टिप्स की बात कर रहे हैं, जिसे अपनाकर आप अपने प्रेम जीवन को मधुर और प्रगाढ़ बना सकते हैं। यह फेंगशुई टिप्स खासतौर पर बेडरूम के लिए है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो वे दिक्कतें भी इस उपाय से आसानी से दूर होंगी।

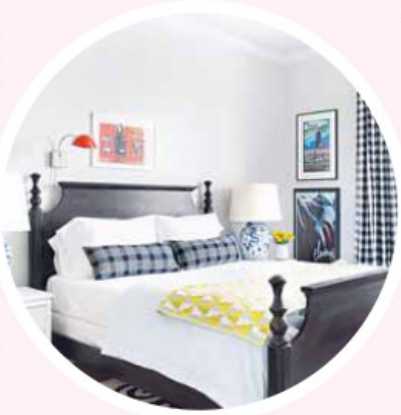

फेंगशुई के अनुसार अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपने बेडरूम में टी.वी, कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को न रखें।

फेंगशुई में बेड के सामने टॉयलेट का गेट न होने की सलाह दी गई है। अगर ऐसा हो भी तो हमेशा बंद रखें।

बेड के सामने कभी-भी मिरर नहीं होना चाहिए। फेंगशुई के मुताबिक इससे पति-पत्नी में तकरार होने की संभावना बनी रहती है।

डबल बेड पर सिंगल गद्दे इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ते में आई नकारात्मकता दूर होती है और दोनों का रिश्ता मजबूत होता है।

बेड को हमेशा सिरा खिड़की या दीवार से हटा कर रखें। दीवार से सटा कर रखने से संबंधों में तनाव पैदा होता है।

बेड के नीचे किसी भी तरह का सामान नहीं रखें। इससे बेडरूम में सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो अच्छा रहेगा।

परेशानियों से बचने के लिए घर में रखें फेंगशुई ऊंट

अगर आप बुरे वक्त के दौर से गुजर रहे हैं, तो घर में फेंगशुई गैजेट ऊंट की स्थापना करें। यह आपको परेशानियों से निजात दिलाएगा।

> अगर आपके परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है या परिवार के किसी सदस्य को बीमारी, दुर्घटना आदि का खतरा बना रहता है, तो यह गैजेट निश्चित रूप से उसके लिए सहायक साबित हो सकता है।

समझदार वही है, जो बुरे दिनों के लिए पहले से तैयार रहता है। बात चाहे रुपए-पैसे की हो या स्वास्थ्य की, आर्थिक तंगी से निपटने के लिए हम नियमित बचत करते हैं तो बीमारी, रोग आदि के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं।

यह बताने की जरूरत नहीं कि ये सब चीजें बुरे समय में हमारे कितनी काम आती हैं। आज फेंगशुई के जिस गैजेट के बारे में बता रहे हैं, वह न सिर्फ बुरे समय में हमारे लिए सहायता का काम करता है, बल्कि उसकी स्थापना हमें आने वाली विपदा व दुर्भाग्य से भी बचाती है। यह गैजेट है फेंगशुई ऊंट। जिस तरह यह जानवर विलक्षण क्षमताओं वाला है, उसी प्रकार फेंगशुई गैजेट के रूप में भी इसके प्रभाव विलक्षण हैं। ऊंट एकमात्र ऐसा जानवर है, जो विपरीत परिस्थितियों में कई दिनों तक बिना खाए-पीए रहकर भी अपने सवार को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है।

अगर आपके परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है या परिवार के किसी सदस्य को बीमारी, दुर्घटना आदि का खतरा बना रहता है, तो यह गैजेट निश्चित रूप से उसके लिए सहायक साबित हो सकता है।

हमारी आधी से अधिक चिंताओं और परेशानियों की वजह होती है आर्थिक समस्या। आपको अपने निवेश का उचित प्रतिफल मिले और आपके पास कैश फ्लो यानी नगद की आवक बनी रहे तो इसके लिए फेंगशुई ऊंट को घर के उत्तर-पश्चिम में स्थापित करना चाहिए।

Palmistry

हस्तरेखाएं बताती हैं विवाह की कुंडली

हस्तरेखा ज्योतिष की सहायता से हथेलियों पर बनी रेखाओं से व्यक्ति के पूरे जीवन में होने वाली कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में मालूम किया जा सकता है। हथेली पर कई तरह की रेखाएं बनती हैं जिसमें जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा और विवाह रेखा प्रमुख होती है। जीवन और भाग्य रेखा जहां व्यक्ति के जीवन और उसके भाग्य के बारे में जानकारी देते हैं, तो वहीं विवाह रेखा से व्यक्ति के प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन के बारे में पता चलता है।

विवाह रेखा में कई बाते होती हैं। जैसे आपकी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज और शादियों का योग कितना है?

कहां होती है विवाह रेखा

हथेली पर विवाह रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे वाले भाग पर जहां बुध पर्वत बना होता है वहां पर आड़ी स्थिति में होती है। इस जगह पर विवाह रेखा एक या एक से अधिक भी हो सकती है।

विवाह रेखा से जुड़ी खास बातें

हथेली में बुध पर्वत के पास विवाह रेखा लंबी, सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए। जो विवाह रेखा हृदय रेखा के बराबर चलती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।

हथेली पर एक से ज्यादा विवाह रेखा बनने पर यह कई प्रेम प्रसंग की तरफ इशारा करता है।

विवाह रेखा में दो शाखाएं निकली हुई हो तो उस व्यक्ति की शादी टूटने का भय रहता है।

अगर किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा के पास द्वीप का निशान बना हुआ हो तो विवाह में किसी धोखे से होने की संभावनाएं रहती हैं।

अगर किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा झुकी हुई दिखाई दे रही है यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है।

विवाह रेखा अगर लम्बी और सूर्य पर्वत तक जाए तो यह संपन्न और समृद्ध जीवन साथी का प्रतीक है।

अगर विवाह रेखा को कोई रेखा बुध पर्वत पर काट दे तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन परेशानियों भरा होता है।

विवाह रेखा अगर बीच में टूटी हो तो यह विवाह टूटने का संकेत माना जाता है।

विवाह रेखा पर त्रिशूल का निशान बनने पर पति-पत्नी के बीच काफी प्रेम भाव होता है।

करॉना वायरस से दुनिया में खौफ

अब तक 9 की मौत, भारत में खास जांच

नई दिल्ली। एजेंसी

चीन में फैला करॉना वायरस अब दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एशिया के कई देशों में इस वायरस के फैलने की खबर ने दुनियाभर के देशों को चौकन्ना कर दिया है। इस जानलेवा वायरस से अबतक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियां इस बीमारी को फैलने से रोकने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। भारत में भी इस बीमारी को लेकर काफी सर्तकता बरती जा रही है। देश के 7 हवाईअड्डों पर चीन और हॉन्ग कॉन्ग से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है।

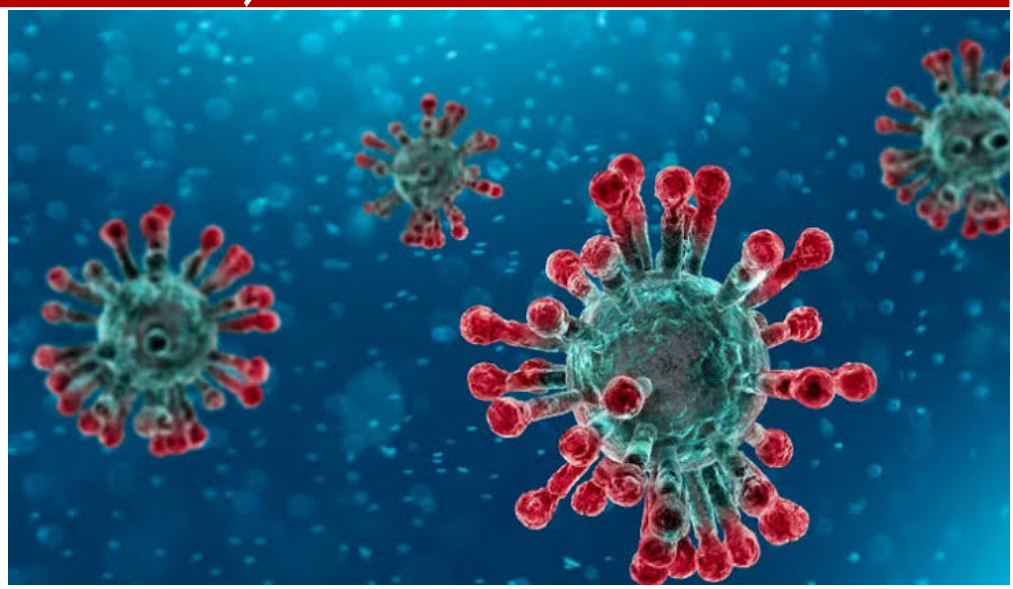

भारत भी हुआ चौकन्ना

करॉना वायरस वायरस पर भारत भी चौकन्ना हो गया है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने मंगलवार को देश के 7 हवाईअड्डो चेन्नै, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता को चीन और हॉन्ग कॉन्ग से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग का आदेश दिया है। एयरलाइंस के कर्मचारी इन हेल्थ काउंटर पर लोगों को लाएंगे। अगर कोई शख्स या विमानकर्मी में वायरस से जुड़ा कोई संकेत पाए जाएंगे तो इस बारे में स्वास्थ्य कर्मचारियों को जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ मंत्रालय के आदेश के बाद विमानन मंत्रालय ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के लिए ऐक्शन प्लान तैयार किया है और उसके पालन करने में सख्ती बरती जा रही है।

अमेरिका में वायरस से पीड़ित एक शख्स की पहचान

उधर, अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि वॉशिंगटन में इस वायरस से पीड़ित से एक शख्स की पहचान हुई है। वह शख्स हाल ही में चीन की यात्रा से लौटा था। दक्षिण कोरिया, जापान और थाइलैंड में भी इस खतरनाक वायरस से पीड़ित 4 मामले सामने आए हैं। ताइवान का एक करोबारी में यह वायरस पाया गया है। वह कुछ दिन पहले ही चीन के वुहान प्रांत की यात्रा से लौटे थे।

वुहान के लोगों को शहर नहीं छोड़ने को कहा गया है WHO की आपात बैठक

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि यह वायरस कितना खतरनाक है और कैसे फैल रहा है। इस बीच, जिस तेजी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद से सभी देश इस बीमारी से पीड़ित लोगों की पहचान की कोशिशें तेज कर दी है। मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस बात पर चर्चा की कि क्या इसे वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया जाए।

रूस ने सीमा पर सख्ती बढ़ाई

इस बीच, रूस ने चीन से लगती अपनी सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है जबकि, अमेरिकी ने अपने हवाईअड्डों पर चीन से आने वाले लोगों की जांच के लिए चेक पॉइंट्स बनाए हैं।

क्या होता है करॉना वायरस

करॉना वायरस आमतौर पर जानवरों में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई बार जानवरों से इसका संचार इंसानों में भी हो जाता है। इस वायरस से ग्रसित होने पर श्वास संबंधी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए कोई खास इलाज का इजाद नहीं हो पाया है। कई बार बीमारी के लक्षण खुद-ब-खुद खत्म हो जाते हैं।

लार से फैलता है यह वायरस!

अधिकारियों ने बताया कि यह खतरनाक वायरस लार से भी फैल रहा है। चीन की नैशनल हेल्थ कमिशन ने मंगलवार को कहा कि उसने अभीतक ऐसा कॉरेन वायरस नहीं देखा जो मनुष्यों से फैलता हो। बताया जा रहा है कि ये वायरस लार और कफ के जरिए भी फैल रहे हैं।

वायरस से जुड़ी 10 बातें जान लें

1-पूरे एशिया में करीब 325 लोग इस घातक वायरस से पीड़ित। इसमें 20 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं।

2-अबतक इस वायरस से 6 लोगों की मौत की पुष्टि।

3-उत्तर कोरिया ने अपने देश में सभी पर्यटकों की एंट्री पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई।

4-चीन के स्वास्थ्य आयोग ने वुहान की एक करोड़ से ज्यादा की आबादी को शहर नहीं छोड़ने की अपील की है।

5-WHO ने इस वायरस को लेकर आपात बैठक की। बैठक में इस बीमारी की रोकथाम पर चर्चा की गई।

6-अमेरिका की नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस वायरस के वैक्सीन पर शोध कर रही है। लेकिन मनुष्यों पर इसे परीक्षण में अभी महीनों लग सकते हैं।

7-दुनिया के कुछ जाने माने वैज्ञानिकों ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य वाली चेतावनी बताया है।

8-खतरनाक वायरस के कारण पर्यटकों के देश में नहीं आने के डर में चीन और हॉन्ग कॉन्ग के शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है।

9-रूस, कजाकिस्तान और मलयेशिया जैसे देशों ने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया को सख्त किया।

10-इस बीमारी की फैलने की जांच कर रहे एक मशहूर चीनी डॉक्टर भी वायरस की चपेट में आए।

वैश्विक रुख से वायदा कारोबार में सोना फिसला

नयी दिल्ली। एजेंसी

कमजोर वैश्विक रुख के साथ प्रतिभागियों के सौदे कम करने से बुधवार को वायदा कारोबार में सोना 105 रुपये गिरकर 39,806 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, फरवरी महीने में डिलिवरी वाला सोना 105 रुपये यानी 0.26 प्रतिशत गिरकर 39,806 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया। इसमें 1,373 लॉट का कारोबार हुआ। इसी प्रकार, अप्रैल महीने में डिलिवरी वाला सोना 136 रुपये यानी 0.34 प्रतिशत घटकर 39,895 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया। इसमें 124 लॉट का कारोबार हुआ। विश्लेषकों ने कहा कि वैश्विक बाजारों में पीली धातु को लेकर सुस्त रुख से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.46 प्रतिशत गिरकर 1,550.70 डॉलर प्रति औंस पर रहा।

आसियान सचिवालय ने भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी बैठक के लिये आमंत्रित किया

नयी दिल्ली। आसियान सचिवालय ने बाली में होने वाली क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी बैठक में भाग लेने के लिये भारत को आमंत्रित किया है। यह बैठक 3-4 फरवरी को आरसीईपी समझौते से जुड़ी भारत की चिंताओं को दूर करने के लिये हो रही है। एक अधिकारी ने यह कहा। भारत ने पिछले साल नवंबर में उसकी चिंताओं का उचित समाधान नहीं होने की वजह से बैंकाक में हुये क्षेत्रीय वृहत आर्थिक समझौते से अलग रहने का निर्णय किया था। इसका कारण उसकी चिंताओं का समाधान नहीं होना था।

अधिकारी ने कहा, ''भारत को बैठक के लिये निमंत्रण मिला है लेकिन उसने इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।'' क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते को लेकर आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बातचीत में शामिल थे। इससे पहले जापान ने संकेत दिया था कि भारत को महत्वकांक्षी आरसीईपी में शामिल करने को लेकर प्रयास जारी हैं। उसने कहा था कि समूह में शामिल सभी देश भारत की चिंताओं को दूर करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

Polymer MIS

Market Intelligence Source

In this information age having latest news, information, data and analysis is critical to the success of any business. We at PolymerMIS provide you exactly with this for Polymer and Petrochemical Industries, to help you have an edge over your competitors and stay ahead of them in every segment.

We bring to you on real time basis with breaking news as it happens, including market trends, quotes, moves, analysis, data, predictions and much more. We provide everything you need to know to stay informed and react to changing market conditions.

Advantages of Being with PolymerMIS

• Most important, its Economical. • Information on fingertips - SMS based alerts. • Quickest method of information delivery. • No hassle to browse to reach the content applicable for you. Pay for only what you need. • Covers Wide range of petrochemical products and feedstock including Aromatics, Olefins, crude oil, Polymers etc.

Sample SMS from PolymerMIS

Brent Crude Oil $48.83 US$/Rs.65.66 Propylene $605 CFR China Ethylene $1000 CFR NEA Naphtha $460 CFR Japan Styrene $920 CFR China.

PE market Updates - Intl. market assessed as firm amid short supply and higher Ethylene of 1005$ in SE Asia. November offers for India are above 1200$ for LL/HD/LD. Converters are keeping low inventories due to upcoming festivals and we may see revival of demand after 15th November.

RIL reduced PP Prices by Rs. 2000/MT and PP Random by Rs. 3000/MT Price Protection withdrawn w.e.f. 1 November 2015.

Various Plans we offer

We provide two broad categories of Plans for subscription:-

SMS Plan - In SMS Plan, we provide you SMS based alerts on Market Prices for Various Polymers and Daily Updates on Plants, Crude, Forex, Market Trend and Projections, Market Moves, Corporate Actions, Impact of Global changes etc.

Web Plan - PolymerMIS has emerged one of the Best Web Plan among thousands of our clients in India and across the world. Where our clients will get sms alerts and web access on our portal for Domestic and International Plastic Industry updates, Breaking News, Instant News alerts, Trend Analysis, Technical Analysis, Historic Data, Comparison of various Grades as well as Daily Newsletter, Latest News and Updates of HDPE, LDPE, LLDPE, PP, EVA, PVC, GPPS, HIPS, ABS, SAN and all Feedstock Prices and Market Trends on relevant subjects without cluttering your inbox. We bring whole Polymer industry under your thumb by providing our complimentary Android and ios Services. We want all our customers to have a fantastic experience with our latest news and updates. Our goal is to inform you before anyone else. We always effort to present you the best possible services every time. There's more to know about Polymer industry. Kindly visit at www.polymermis.com

VISTA WEBSOFT PRIVATE LIMITED

Corporate Office:
402 Morya Blue Moon,
B-57 off New Link Road,
Fortune Terrace Lane,
Andheri West, Mumbai -400053, India
Tel.: +91-22-26736570, Fax: +91-22-26736522,
Email: sales@polymermis.com

Branch Office :
2/12, South Tukoganj,
Near Noble Hospital,
Indore, M.P. 452001, India
Tel: +91-731-4068185, Fax: +91-731-4068185,
Email: sales@polymermis.com

Visit us at : www.polymermis.com

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।